NYCS

RNI: DELBIL/2008/25219, ₹20

युवा सहकार

www.nycsindia.com

फरवरी 2025, नई दिल्ली

आम बजट 2025-26

रोजगार बढ़ाने पर फोकस

अंदर के पन्नों पर: इनकम टैक्स में बड़ी राहत

कृषि बनेगा विकास का पहला इंजन

KRIBHCO
Cooperative and beyond...

Azadi Ka Amrit Mahotsav

Did You Know?

2025 is the International Year of Cooperatives!

The UN declared 2025 as a year to celebrate cooperatives around the world. Cooperatives are businesses owned by their members, focusing on both profit and the needs of their communities. They play a big role in sustainable development and achieving the UN's Sustainable Development Goals by 2030.

There will be a year-long celebration to raise awareness about cooperatives and their positive impact.

युवा सहकार

वर्ष : 01, अंक-08, फरवरी-2025

निदेशक मंडल
एनवाईसीएस

प्रकाश चंद्र साहू
मनीष कुमार
राजेश बाबूलाल पांडे
प्रकृति क्षितिज पंड्या
बालू गोपालकृष्णन
ज्योतिर्मय सिंह महतो
गौरव पांडेय
हिरेन मधुसूदन शाह
राघव गर्ग
आशुतोष सतीश गुप्ता

कार्यालय

नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड (एनवाईसीएस)
209, द्वितीय तल, ए2बी, वर्द्धमान जनक मार्केट, जनकपुरी, नई दिल्ली - 110058
मोबाइल नंबर : 9205595944
लैंडलाइन नंबर : 011-45096652/40153681
E-mail: nycs.ltd@gmail.com
Web: www.nycsindia.com

Registration No
DELBIL/2008/25219

संकल्पना, कंटेंट व डिजाइन : फार्च्यूना कम्यूनिकेशंस प्रा. लि., नई दिल्ली

नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित एवं पारस ऑफसेट प्रा. लि. कुंडली, हरियाणा द्वारा मुद्रित।

अभिषेक कुमारः पीआरबी एक्ट के तहत खबरों के चयन के उत्तरदायी।

NYCSIndia

परिवर्तनकारी सुधारों से सुस्ती होगी दूर 04

कुशल पेशेवरों की नई पीढ़ी हो रही तैयार 05

06 मैन्युफैक्चरिंग और खपत पर जोरः रोजगार बढ़ाने पर फोकस

16 सहकारिता में मजबूत होता सहकार

युवाओं को प्रशिक्षण पर फोकस 18

कोऑपरेटिव बैंकों में मिलेंगी सभी सेवाएं 21

इनोवेशन आधारित होंगी भविष्य की नौकरियां 22

एनसीएस पोर्टल से हर साल मिलेंगी 11 लाख नौकरियां 24

किताबों का कोई विकल्प नहीं 26

विकास, नवाचार और युवा सशक्तिकरण को बढ़ावा 28

कौशल प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को प्रमाण-पत्र 30

परिवर्तनकारी सुधारों से सुस्ती होगी दूर

बजट में भारत की विकास संभावनाओं और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि के लिए टैक्स व्यवस्था, ऊर्जा क्षेत्र, ग्रामीण विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र और नियामकों में परिवर्तनकारी सुधारों का लक्ष्य रखा गया है। वित्त मंत्री ने कृषि, एसएसएमई, निवेश और निर्यात को विकसित भारत की यात्रा के चार प्रमुख इंजन बताए हैं। इसमें सुधार को ईंधन के रूप में और समावेशिता की भावना को पथप्रदर्शक के रूप में रखा गया है।

घरेलू और विदेशी कारकों की वजह से विभिन्न चुनौतियों से जूझ रही अर्थव्यवस्था की रफ्तार को सुस्त होने से बचाए रखना केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए मुश्किलों भरा रहा है। 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरी है कि अर्थव्यवस्था लगातार तेज गति से दौड़ती रहे। मगर पिछले कुछ समय से विकास दर में सुस्ती इस राह में रोड़े अटकाने वाला साबित हो रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है मांग और खपत में कमी जो महंगाई, घटती आय और बेरोजगारी से प्रभावित है।

केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकारी प्रयासों को जारी रखने, समग्र विकास को सुनिश्चित करने, निजी निवेश को बढ़ाने और उभरते मध्यम वर्ग की व्यय क्षमता को बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। गरीब, युवा, किसान और महिला को ध्यान में रखकर विकास को बढ़ाने वाले उपाय किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताओं में भी ये चार वर्ग हैं। बजट में भारत की विकास संभावनाओं और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि के लिए टैक्स व्यवस्था, ऊर्जा क्षेत्र, ग्रामीण विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र और नियामकों में परिवर्तनकारी सुधारों का लक्ष्य रखा गया है। वित्त मंत्री ने कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात को विकसित भारत की यात्रा के चार प्रमुख इंजन बताए हैं। इसमें सुधार को इंजन के रूप में और समावेशिता की भावना को पथप्रदर्शक के रूप में रखा गया है।

मांग में कमी अर्थव्यवस्था के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्रभावित कर रही है। देश का मध्य वर्ग सबसे बड़ा उपभोक्ता वर्ग है जो महंगाई और घटती आय से परेशान है। इसे ध्यान में रखते हुए ही वित्त मंत्री ने 12.75 लाख रुपये तक की आमदनी को इनकम टैक्स से छूट दे दी है। वरिष्ठ नागरिकों को अलग से टैक्स राहत दी गई है। इससे लोगों की जेब में पहले की तुलना में ज्यादा पैसा बचेगा जिससे मांग बढ़ने की संभावना है। मांग बढ़ेगी तो इंडस्ट्री के पहिए तेज घूमेंगे जिससे रोजगार के भी नए अवसर बनेंगे।

रोजगार के अवसर बढ़ाना केंद्र सरकार के लिए हमेशा से चुनौती रही है। 2024-25 के बजट में इसके लिए ठोस उपाय किए गए थे जिसे 2025-26 के बजट में भी जारी रखने का प्रयास किया गया है। खिलौना निर्माण, फुटवियर, पर्यटन, एमएसएमई सहित स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के बजटीय प्रावधानों से रोजगार के मोर्चे पर राहत मिलने की उम्मीद है। इन्फ्रास्ट्रक्चर की श्रेणी में 50 पर्यटन स्थलों पर होटलों को शामिल करने से पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा, जिससे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, जो सबसे बड़ा रोजगार क्षेत्र है, को नई ऊर्जा मिलेगी। एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी कवर को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये करने का ऐलान किया गया है जिससे अगले 5 साल में एमएसएमई को 1.5 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण उपलब्ध होगा। इससे इस क्षेत्र का विस्तार होगा और नौकरियों की संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी।

निर्मला सीतारमण ने कृषि और इससे संबद्ध क्षेत्र को देश के विकास का पहला इंजन मानते हुए आम बजट में इसे प्राथमिकता दी है। भारत की विकास संभावनाओं और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए कृषि को और प्रोत्साहन की आवश्यकता है। इसके लिए प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। इस समग्र योजना के तहत कृषि उत्पादन के मामले में देश के पिछड़े जिलों में फसलों की उत्पादकता बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा, किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ब्याज सब्सिडी वाले कर्ज की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने, मखाना बोर्ड बनाने जैसे प्रावधान कृषि क्षेत्र को नई दिशा देने वाले साबित हो सकते हैं।■

प्रकाश चंद्र साहू
अध्यक्ष, नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड

कुशल पेशेवरों की नई पीढ़ी हो रही तैयार

युवा सहकार टीम

देश में कुशल पेशेवरों की अगली पीढ़ी तैयार करने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना युवाओं को काफी आकर्षित कर रही है। रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में शुरू की गई इस योजना के तहत अगले पांच वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को देश की टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। इस योजना की घोषणा वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में की गई थी।

इस योजना की शुरूआत के रूप में कॉरपोरेट मंत्रालय ने 3 अक्टूबर, 2024 को पायलट परियोजना शुरू की। पायलट प्रोजेक्ट के पहले दौर में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 745 जिलों में भागीदार कंपनियों द्वारा 1.27 लाख से अधिक इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए गए। इसके लिए लगभग 6.21 लाख युवाओं ने आवेदन किए। इनमें से 60,866 उम्मीदवारों को विभिन्न क्षेत्र की कंपनियों द्वारा 82,077 इंटर्नशिप ऑफर किए गए, जिनमें से 28,141 उम्मीदवारों ने ऑफर स्वीकार किए। पायलट प्रोजेक्ट का दूसरा दौर 9 जनवरी से शुरू हो गया है। कंपनियां नए इंटर्नशिप अवसरों की पेशकश के साथ-साथ खाली पड़े इंटर्नशिप अवसरों को भी भरने की प्रक्रिया में हैं। पायलट प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के लिए सरकार ने 840 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। कॉरपोरेट मंत्रालय की ओर से संसद में यह जानकारी दी गई है।

पायलट प्रोजेक्ट के दिशानिर्देशों के अनुसार, देश के सभी हिस्सों से प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर उम्मीदवारों के एक पूल को पीएम इंटर्नशिप पोर्टल के माध्यम से प्रत्येक इंटर्नशिप अवसर के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। शॉर्टलिस्टिंग प्रक्रिया का उद्देश्य संबंधित कंपनी को उनकी संबंधित प्रक्रियाओं और मानदंडों के अनुसार आगे के चयन के लिए भेजी गई शॉर्टलिस्ट में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों के साथ-साथ दिव्यांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व प्रदान करके इंटर्नशिप कार्यक्रम में विविधता और सामाजिक समावेशिता को बढ़ावा देना है।

यह योजना रोजगार के अवसरों को बढ़ाने का एक परिवर्तनकारी प्रयास है जो नियोक्ताओं और प्रतिभागियों दोनों के लिए बेहतर है। इसका उद्देश्य युवा उम्मीदवारों को उद्योग जगत से जोड़कर कार्यबल में कौशल अंतर को दूर करना और प्रतिभागियों को भविष्य के नौकरी बाजार के लिए तैयार करना है। इस योजना के तहत इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को 12 महीने तक हर महीने 5,000 रुपये देने का प्रावधान है। इसमें से 4,500 रुपये केंद्र सरकार की ओर से और 500 रुपये कंपनी की ओर से दिए जाते हैं। यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। इसके अलावा, सरकार उन्हें 6,000 रुपये की एकमुश्त सहायता देती है। साथ ही, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत उनका बीमा भी किया जाता है।

पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए भागीदार कंपनियों में पिछले 3 वर्षों में औसत कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) व्यय के आधार पर चयनित शीर्ष 500 कंपनियां शामिल हैं। इनमें विमानन और रक्षा, मोटर वाहन, बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं, रासायनिक उद्योग, तेल, गैस और ऊर्जा आदि सहित बड़ी संख्या में विविध क्षेत्रों की कंपनियां शामिल हैं।

इस योजना के तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की उम्र 21-24 वर्ष होनी चाहिए। दसवीं, बारहवीं, आईटीआई, पॉलिटेक्निक डिप्लोमाधारी और ग्रेजुएट (बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीफार्मा) युवक-युवती इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर कोई कहीं से फुल टाइम कोर्स या फुल टाइम जॉब कर रहा हो तो वह इसके लिए आवेदन नहीं कर सकता। डिस्टेंस लर्निंग वाले आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, आवेदक के परिवार (खुद/पति या पत्नी/ माता-पिता) की सालाना आमदनी 8 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही, परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में न हो। आवेदन करने के बाद कंपनियां खुद ही आपसे संपर्क कर इंटर्नशिप के लिए बुलाएंगी। ■

आम बजट
2025-26

मैन्युफैक्चरिंग और खपत पर जोर

रोजगार बढ़ाने पर फोकस

वेतनभोगी मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग में खपत को बढ़ावा देने के लिए 12 लाख रुपये तक की आमदनी को इनकम टैक्स से छूट दे दी गई है। मौजूदा सरकार के 10 वर्ष के कार्यकाल में यह पहली बार है जब मध्य वर्ग को इतनी बड़ी सौगात मिली है और एक झटके में 5 लाख रुपये की इनकम टैक्स छूट दी गई है।

अभिषेक राजा

बजट सत्र शुरू होने से ऐन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद परिसर में कहा था, 'मैं धन और समृद्धि की देवी देवी लक्ष्मी को नमन करता हूं। मैं देवी लक्ष्मी से

प्रार्थना करता हूं कि वे गरीबों और मध्यम वर्ग पर अपनी कृपा बरसाएं।' उनके इस बयान के साथ ही यह कयास लगाए जाने लगे थे कि इस बार के बजट में कुछ ऐसी घोषणा हो सकती है जो आम लोगों को बड़ी राहत देने वाली होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री के इस बयान को सच साबित करते हुए मध्य वर्ग के लिए आयकर में छूट का पिटारा खोल दिया जिससे उनकी जेब में अब पहले से ज्यादा पैसा बचेगा जो मांग बढ़ाने में मददगार होगा। रही सही कसर आम बजट पेश होने के छह दिन बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने पूरी कर दी। रिजर्व बैंक ने पांच साल बाद पहली बार रेपो रेट में चौथाई फीसदी की कटौती की जिससे न सिर्फ लोन की मासिक किस्त घटने की संभावना है, बल्कि कंपनियों को भी सस्ता कर्ज मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

भारतीय मध्य वर्ग देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता वर्ग है। यही वह वर्ग है जिसकी खपत और मांग के आधार पर मैन्युफैक्चरिंग, सेवा सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों की दिशा तय होती है। पिछले काफी समय से यह वर्ग महंगाई, बेरोजगारी और घटती आय से जूझ रहा है। इसकी वजह से घरेलू खपत में कमी आई है। खपत घटी तो मांग में कमी आई, मांग घटी तो मैन्युफैक्चरिंग घट गई, मैन्युफैक्चरिंग कम हुई तो कंपनियों ने निवेश घटा दिया जिससे विस्तार की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। इसकी वजह से रोजगार पर असर पड़ा और जीडीपी की समग्र वृद्धि दर घट गई। इस बड़ी समस्या ने सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए ही वित्त मंत्री ने तय किया कि खपत और रोजगार बढ़ाने पर फोकस किया जाए। खपत तभी बढ़ेगी जब लोगों की जेब में पैसा बचेगा। बजटीय समर्थन और आरबीआई के ब्याज दर घटाने के फैसलों का व्यापक असर पड़ेगा जो खपत बढ़ाने वाला साबित होगा।

वेतनभोगी मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग में खपत को बढ़ावा देने के लिए 12 लाख रुपये तक की आमदनी को इनकम टैक्स से छूट दे दी गई है। मौजूदा सरकार के 10 वर्ष के कार्यकाल में यह पहली बार है जब मध्य वर्ग को इतनी बड़ी सौगात मिली है और एक झटके में 5 लाख रुपये की इनकम टैक्स छूट दी गई है। आर्थिक सर्वेक्षण में भी बताया गया था कि 2024-25 में ग्रामीण क्षेत्रों में खपत में लगातार बढ़ोतरी हुई है, जबकि शहरों में मांग में मिला-जुला रुझान देखने को मिला है। यह कदम इसी समस्या का समाधान करने के लिए उठाया गया है। इसके अलावा, मध्य वर्ग लंबे समय से इनकम टैक्स में छूट देने की मांग कर रहा था क्योंकि महंगाई और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के बढ़ते बोझ से लोगों की आमदनी सीमित हो गई थी।

UNION BUDGET 2025-26

- 1 लाख रुपये तक प्रति माह की औसत आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं, मध्य वर्गीय परिवारों की आय व खपत में वृद्धि होगी
- कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात विकास के चार इंजन
- प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना से 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे, 100 पिछड़े जिले होंगे शामिल
- अरहर, उड़द व मसूर पर विशेष ध्यान देते हुए 'दालों में आत्मनिर्भरता मिशन' शुरू किया जाएगा
- किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अब किसानों को ब्याज सब्सिडी वाला पांच लाख रुपये तक का लोन मिलेगा
- वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा 4.8 प्रतिशत रहने का अनुमान जिसे वित्त वर्ष 2025-26 में घटाकर 4.4 प्रतिशत करने का लक्ष्य
- एमएसएमई को गारंटी के साथ दिए जाने वाले कर्ज को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये किया गया
- मेक इन इंडिया को निरंतरता देने के लिए लघु, मध्यम व बड़े उद्योग को शामिल कर राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन का शुभारंभ
- गिग वर्करों को पहचान पत्र दिया जाएगा, पीएम जन आरोग्य योजना के तहत ई-श्रम पोर्टल और स्वास्थ्य देखभाल में उनका होगा पंजीकरण
- बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा 74 से बढ़ाकर 100 प्रतिशत की गई
- कैंसर, असाधारण रोगों और अन्य गंभीर रोगों के उपचार के लिए 36 जीवनरक्षक औषधियों को बुनियादी सीमा शुल्क (बीसीडी) से छूट

> **इन्फ्रास्ट्रक्चर की श्रेणी में 50 पर्यटन स्थलों पर होटलों को शामिल करने से पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा, जिससे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, जो सबसे बड़ा रोजगार क्षेत्र है, को नई ऊर्जा मिलेगी। आध्यात्मिक व धार्मिक महत्वों के स्थलों और भगवान बुद्ध के जीवन काल से जुड़े स्थलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।**

खपत बढ़ने से बढ़ेगा रोजगार

खपत बढ़ेगी तो उपभोक्ता मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा जिससे कंपनियां विस्तार करेंगी। कंपनियां विस्तार करेंगी तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। रोजगार बढ़ेंगे तो फिर से खपत में तेजी आएगी और यह चक्र चलता रहेगा। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में भी युवाओं के लिए रोजगार बढ़ाने संबंधी कई तरह की घोषणाएं की गई थी जिसे जारी रखने का प्रयास 2025-26 के बजट में भी किया गया है। इसके तहत पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने वाले कदमों के साथ पीएलआई (प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेटिंव) स्कीम को बढ़ाने और लघु एवं छोटे उद्योगों (एमएसएमई) के लिए नए प्रावधान किए गए हैं। बजट में सभी रोजगार क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है।

पर्यटन बढ़ाएगा नए अवसर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि केंद्रीय बजट 2025-26 ने पर्यटन को रोजगार प्रेरित विकास के रूप में स्थापित किया है। रोजगार आधारित विकास हेतु युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम की पहल की गई है। इसके साथ ही होमस्टे के लिए मुद्रा लोन, यात्रा सुगमता में सुधार और पर्यटन स्थलों तक संपर्क, ई-वीजा सुविधा में सरलीकरण और राज्यों को प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन जैसे उपाय भी किए गए हैं। राज्यों के सहयोग से देश में 50 पर्यटन स्थल विकसित किए जाएंगे। होटल व अन्य प्रमुख इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए भूमि की व्यवस्था राज्यों द्वारा की जाएगी और इन क्षेत्रों में बनने वाले होटलों को इन्फ्रास्ट्रक्चर में शामिल किया जाएगा। इन्फ्रास्ट्रक्चर की श्रेणी में 50 पर्यटन स्थलों पर होटलों को शामिल करने से पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा, जिससे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, जो सबसे बड़ा रोजगार क्षेत्र है,

एनसीडीसी देगा ज्यादा कर्ज

सहकारी संस्थाओं, बैंकों और सहकारी चीनी मिलों को कार्यशील पूंजी और सावधि ऋण उपलब्ध कराने वाली राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) अब पहले से ज्यादा कर्ज दे सकेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में सहकारी समितियों को मजबूत करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सहकारी क्षेत्र के लिए ऋण संचालन को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) को सरकारी समर्थन की घोषणा की। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और ग्रामीणों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी।

एनसीडीसी के लिए समर्थन की घोषणा करते हुए सीतारमण ने कहा, 'हमारी सरकार सहकारी क्षेत्र के ऋण संचालन के लिए एनसीडीसी को सहायता प्रदान करेगी।' उन्होंने सहकारी चीनी मिलों को मजबूत करने के लिए एनसीडीसी को अनुदान सहायता के रूप में 500 करोड़ रुपये आवंटित किए। इस योजना के तहत केंद्र सरकार सहकारी चीनी मिलों को 10,000 करोड़ रुपये तक का ऋण प्रदान करने के लिए एनसीडीसी को 500-500 करोड़ रुपये की दो किस्तों में 1,000 करोड़ रुपये का अनुदान दे रही है।

एनसीडीसी से कर्ज पाने वाली सहकारी समितियों में कृषि ऋण सहकारी समितियां (पैक्स), जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी), राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी), प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (पीसीएआरडी), राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडी), महिला स्वयं सहायता समूह का सहकारी संघ और सहकारी चीनी मिलें शामिल हैं। एनसीडीसी से कर्ज लेने के लिए सहकारी समितियों को कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं। सहकारी समितियों को ऋण देने के साथ-साथ एनसीडीसी उन्हें सब्सिडी भी देता है।

को नई ऊर्जा मिलेगी। आध्यात्मिक व धार्मिक महत्वों के स्थलों और भगवान बुद्ध के जीवन काल से जुड़े स्थलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। क्षमता निर्माण और वीजा नियमों को सरल बनाने के साथ-साथ निजी क्षेत्र के सहयोग से चिकित्सा पर्यटन और स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा दिया जाएगा। आने वाले समय में महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाला एक और बड़ा सुधार, जहाज निर्माण को इन्फ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देने से भारत में बड़े जहाजों के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और आत्मनिर्भर भारत अभियान में तेजी आएगी।

एमएसएमई पर फोकस

रोजगार देने के मामले में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) सबसे आगे हैं। देश में करीब 5.7 करोड़ एमएसएमई हैं, जिनका अर्थव्यवस्था में अहम योगदान है। देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 36 प्रतिशत योगदान एमएसएमई का है जिनमें लगभग 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है। निर्यात में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी 45 प्रतिशत है। पिछले कुछ सालों से बजट में इस क्षेत्र की अनदेखी की जा रही थी या फिर इसे पर्याप्त बजटीय समर्थन नहीं मिल रहा था। इस बार वित्त मंत्री ने एमएसएमई सेक्टर पर विशेष फोकस रखा और इसके लिए ऋण गारंटी कवर को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये करने का ऐलान किया। इससे अगले 5 साल में एमएसएमई को 1.5 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण उपलब्ध होगा जिससे इस क्षेत्र का विस्तार होगा और नौकरियों की संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी। यही नहीं, मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए एमएसएमई और बड़े उद्योगों को शामिल कर राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना की जाएगी। यह केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों के लिए नीतिगत सहायता, निष्पादन कार्ययोजनाएं, शासन और निगरानी फ्रेमवर्क उपलब्ध कराएगा। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन पांच महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे व्यवसाय करने की सुगमता और लागत, मांग वाली नौकरियों के लिए भावी तैयार कार्यबल, जीवंत और गतिशील एमएसएमई क्षेत्र, प्रौद्योगिकी की उपलब्धता और गुणवत्ता युक्त उत्पाद पर बल देगा।

एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी कवर को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये करने का ऐलान किया। इससे अगले 5 साल में एमएसएमई को 1.5 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण उपलब्ध होगा जिससे इस क्षेत्र का विस्तार होगा और नौकरियों की संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी।

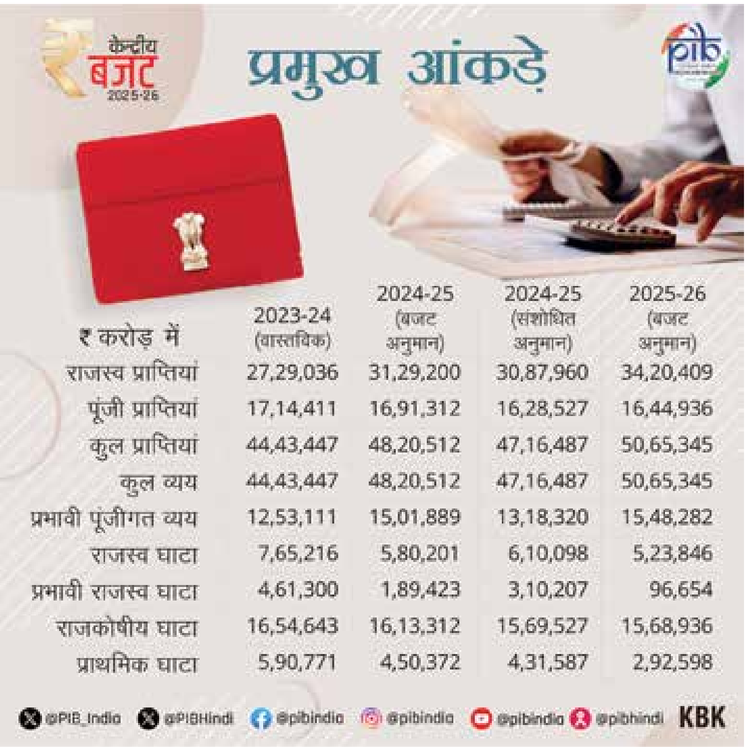

केन्द्रीय
बजट
2025-26

प्रमुख आंकड़े

₹ करोड़ में	2023-24 (वास्तविक)	2024-25 (बजट अनुमान)	2024-25 (संशोधित अनुमान)	2025-26 (बजट अनुमान)
राजस्व प्राप्तियां	27,29,036	31,29,200	30,87,960	34,20,409
पूंजी प्राप्तियां	17,14,411	16,91,312	16,28,527	16,44,936
कुल प्राप्तियां	44,43,447	48,20,512	47,16,487	50,65,345
कुल व्यय	44,43,447	48,20,512	47,16,487	50,65,345
प्रभावी पूंजीगत व्यय	12,53,111	15,01,889	13,18,320	15,48,282
राजस्व घाटा	7,65,216	5,80,201	6,10,098	5,23,846
प्रभावी राजस्व घाटा	4,61,300	1,89,423	3,10,207	96,654
राजकोषीय घाटा	16,54,643	16,13,312	15,69,527	15,68,936
प्राथमिक घाटा	5,90,771	4,50,372	4,31,587	2,92,598

@PIB_India @PIBHindi @pibindia @pibindia @pibindia @pibhindi KBK

फुटवियर और लेदर क्षेत्र की उत्पादकता, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए फोकस उत्पाद स्कीम कार्यान्वित की जाएगी। इस स्कीम में लेदर फुटवियर और अन्य उत्पादों के लिए सहायता के अलावा बिना लेदर वाले गुणवत्तापूर्ण फुटवियर के उत्पादन हेतु आवश्यक डिजाइन क्षमता, घटक विनिर्माण और मशीनों के लिए सहायता दी जाएगी। इस स्कीम से 22 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलने, 4 लाख करोड़ रुपये का कारोबार और 1.1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निर्यात होने की उम्मीद है। इसी तरह, भारत को वैश्विक खिलौना केंद्र बनाने के लिए राष्ट्रीय खिलौना कार्य योजना कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव बजट में किया गया है। इस योजना में क्लस्टरों, कौशलों और ऐसे विनिर्माण इको-सिस्टम के विकास पर जोर दिया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप उच्च गुणवत्ता वाले ऐसे अनूठे, नवीन और पर्यावरण अनुकूल खिलौने बनेंगे जो मेड इन इंडिया ब्रांड का प्रतिनिधित्व करने के अलावा रोजगार को भी बढ़ावा देंगे।

स्टार्टअप्स को बढ़ावा

स्टार्टअप इंडिया योजना को प्रोत्साहन मिलने से पिछले कुछ सालों में स्टार्टअप की संख्या में न सिर्फ उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, बल्कि ये नौकरियां देने के मामले में भी अग्रणी साबित हो रहे हैं। देश में इस समय 1.5 लाख से अधिक स्टार्टअप्स हैं जिनमें 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न हैं। इन स्टार्टअप्स ने 16 लाख से ज्यादा नौकरियों के नए अवसर पैदा किए हैं। इसे ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री ने 10,000 करोड़ रुपये के सरकारी योगदान से नया स्टार्टअप फंड बनाने की घोषणा बजट में की। अगली पीढ़ी के स्टार्टअप को प्रेरित करने के लिए डीप टेक फंड पर भी विचार किया जाएगा। स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये कर दिया गया है। आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण 27 प्रमुख क्षेत्रों में ऋणों के लिए गारंटी शुल्क को कम करके एक प्रतिशत करने की घोषणा की गई है। छोटी कंपनियों और स्टार्टअप्स के लिए स्पेशल क्रेडिट कार्ड जारी होगा जिसकी लिमिट 5 लाख रुपये होगी। पहले साल में 10 लाख क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।

महिला उद्यमियों को 2 करोड़ का टर्म लोन

निर्मला सीतारमण ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की पांच लाख महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए नई योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत अगले 5 वर्षों के दौरान महिलाओं को 2 करोड़ रुपये तक का टर्म लोन बिना गारंटी के आसान शर्तों पर दिया जाएगा ताकि वे छोटे और मध्यम स्तर के व्यवसाय शुरू कर सकें। इस योजना में स्टैंड-अप इंडिया स्कीम से प्राप्त सफल अनुभवों को शामिल किया जाएगा। उद्यमशीलता और प्रबंधकीय कौशलों के लिए ऑनलाइन क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इसके तहत उन्हें अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल ट्रेनिंग, मार्केटिंग सपोर्ट और सरकारी योजनाओं से जोड़ने की सुविधा दी जाएगी।

किसानों का ध्यान

बजट में किसान क्रेडिट कार्ड अनुदान योजना के तहत ब्याज सब्सिडी वाले कर्ज की सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5

140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं होंगी पूरी: पीएम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह बजट 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करेगा। इसमें युवाओं के लिए कई क्षेत्र खोले गए हैं। यह बचत, निवेश, खपत और विकास को बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आमतौर पर बजट का ध्यान सरकार के खजाने को भरने पर होता है, लेकिन इस बजट में नागरिकों की जेब भरने, उनकी बचत बढ़ाने और उन्हें देश के विकास में भागीदार बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

इस बजट में सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। परमाणु ऊर्जा में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के ऐतिहासिक फैसले से भविष्य में असैन्य परमाणु ऊर्जा देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान सुनिश्चित करेगी। बजट में सभी रोजगार क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। आने वाले समय में महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाले दो बड़े सुधारों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जहाज निर्माण को इन्फ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देने से भारत में बड़े जहाजों के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और आत्मनिर्भर भारत अभियान में तेजी आएगी। इन्फ्रास्ट्रक्चर की श्रेणी में 50 पर्यटन स्थलों पर होटलों को शामिल करने से पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा, जिससे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, जो सबसे बड़ा रोजगार क्षेत्र है, को नई ऊर्जा मिलेगी। किसानों के लिए की गई घोषणाएं कृषि क्षेत्र और पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई क्रांति की नींव रखेंगी। प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों में सिंचाई और अवसंरचना का विकास किया जाएगा। साथ ही, किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ब्याज सब्सिडी वाले कर्ज की सीमा क 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने से किसानों को अधिक सहायता प्राप्त होगी।

बजट में 12 लाख रुपये तक की आमदनी को टैक्स मुक्त रखने के प्रावधान पर उन्होंने कहा कि सभी आय वर्गों के लिए टैक्स में कटौती की गई है, जिससे मध्यम वर्ग और नई नौकरी पाने वालों को बहुत लाभ होगा। बजट में उद्यमियों, एमएसएमई और छोटे व्यवसायों को मजबूत करने और नई नौकरियां पैदा करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग पर पूरा ध्यान केंद्रित किया गया है। स्वच्छ प्रौद्योगिकी, चमड़ा, फुटवियर और खिलौना उद्योग जैसे क्षेत्रों को नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन के तहत विशेष समर्थन मिला है। एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी को दोगुना किया गया है। एससी, एसटी और महिलाओं के पहली बार के उद्यमियों के लिए बिना गारंटी के 2 करोड़ रुपये तक का ऋण प्रदान करने की योजना की शुरूआत का प्रावधान इस बजट में किया गया है। गिग वर्कर्स का पंजीकरण ई-श्रम पोर्टल पर किया जाएगा ताकि वे स्वास्थ्य सेवा और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठाने में सक्षम हो सकें। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बजट न केवल देश की वर्तमान जरूरतों का समाधान करता है, बल्कि भविष्य की तैयारी में भी मदद करता है।

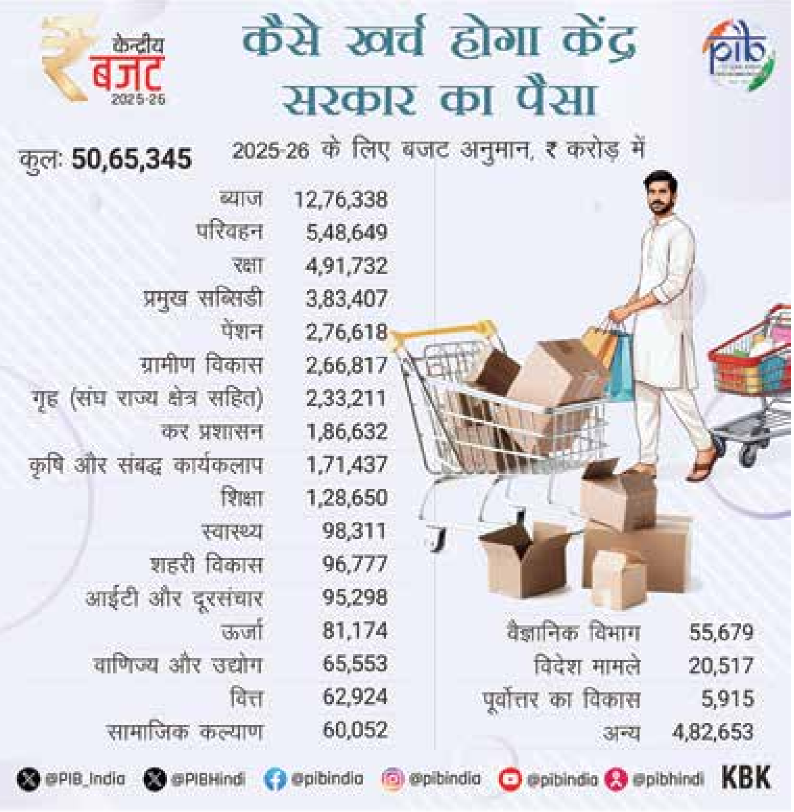

केन्द्रीय
बजट
2025-26

कैसे खर्च होगा केंद्र सरकार का पैसा

कुल: **50,65,345**

2025-26 के लिए बजट अनुमान, ₹ करोड़ में

ब्याज	12,76,338
परिवहन	5,48,649
रक्षा	4,91,732
प्रमुख सब्सिडी	3,83,407
पेंशन	2,76,618
ग्रामीण विकास	2,66,817
गृह (संघ राज्य क्षेत्र सहित)	2,33,211
कर प्रशासन	1,86,632
कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	1,71,437
शिक्षा	1,28,650
स्वास्थ्य	98,311
शहरी विकास	96,777
आईटी और दूरसंचार	95,298
ऊर्जा	81,174
वाणिज्य और उद्योग	65,553
वित्त	62,924
सामाजिक कल्याण	60,052
वैज्ञानिक विभाग	55,679
विदेश मामले	20,517
पूर्वोत्तर का विकास	5,915
अन्य	4,82,653

@PIB_India @PIBHindi @pibindia @pibindia @pibindia @pibhindi KBK

लाख रुपये कर दिया गया है। इसके तहत समय पर भुगतान करने वाले किसानों को 4 फीसदी ब्याज देना होता है, जबकि 3 फीसदी की सब्सिडी मिलती है। वित्त वर्ष 2024-25 में किसान क्रेडिट कार्ड धारकों की संख्या देश में 7.75 करोड़ तक पहुंच गई है। इसके अलावा कम उत्पादकता वाले पिछड़े जिलों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए धन धान्य कृषि योजना शुरू की जाएगी। इसमें 100 जिले शामिल किए जाएंगे जिससे करीब 1.7 करोड़ किसानों को लाभ होगा। बिहार के मखाना उत्पादकों के लिए मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा की गई है। इसके माध्यम से मखाना का उत्पादन बढ़ाने, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्द्धन और मार्केटिंग में सुधार लाया जाएगा।

बजट की प्राथमिकताओं और आवंटनों पर बारीकी से नजर डालें, तो यह साफ होता है कि सरकार ने काफी सतर्क रुख अपनाया है। खपत बढ़ाने और विकास को गति देने के लिए वित्त मंत्री ने दोधारी तलवार का सहारा लिया है। भारी मात्रा में टैक्स छूट से पूंजीगत व्यय पर सार्वजनिक खर्च बढ़ाने की गुंजाइश सीमित हो गई है, जबकि यह भी विकास की रफ्तार बढ़ाने का कारगर तरीका है। लगातार बढ़ रही महंगाई के दौर में मध्य वर्ग के हाथों में ज्यादा पैसा देना सही कदम है। हालांकि, सरकार का मुख्य ध्यान अब भी राजकोषीय संतुलन पर है। वित्त वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटे को 4.4 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके वित्त वर्ष 2024-25 में 4.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

वित्त वर्ष 2025-26 में कुल व्यय 50.65 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि कुल प्राप्तियां 34.96 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। बजट में निवल कर प्राप्तियां 28.37 लाख करोड़ रुपये और सकल बाजार उधारियां 14.82 लाख करोड़ रहने का अनुमान लगाया गया है। वित्त वर्ष 2025-26 में पूंजीगत खर्च 11.21 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है जो जीडीपी का 3.1 प्रतिशत है।■

> **टैक्स छूट से पूंजीगत व्यय पर सार्वजनिक खर्च बढ़ाने की गुंजाइश सीमित हो गई है, जबकि यह भी विकास की रफ्तार बढ़ाने का कारगर तरीका है। लगातार बढ़ रही महंगाई के दौर में मध्य वर्ग के हाथों में ज्यादा पैसा देना सही कदम है। हालांकि, सरकार का मुख्य ध्यान अब भी राजकोषीय संतुलन पर है। वित्त वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटे को 4.4 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके वित्त वर्ष 2024-25 में 4.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है।**

इनकम टैक्स में बड़ी राहत

युवा सहकार टीम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लंबे समय से यह आरोप लगता रहा है कि वह मध्य वर्ग का वोट तो ले लेते हैं, लेकिन बदले में उन्हें कुछ नहीं देते हैं। हर साल मध्य वर्गीय तबका यह बाट जोहता रहता था कि बजट के पिटारे से उसके लिए कुछ निकलेगा, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती थी। महंगाई से जूझ रहे मध्य वर्ग और नौकरीपेशा लोगों को इस बार के बजट में बड़ी राहत देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी को टैक्स फ्री करने की घोषणा की। इसके अलावा, 75 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा। यानी अब 12.75 लाख रुपये तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।

हालांकि, यह छूट नई टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले टैक्सपेयर्स के लिए ही है। पुरानी टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुनने वालों को इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। मगर एक सच्चाई यह भी है कि इस आकर्षक राहत से पुरानी टैक्स व्यवस्था अब बेमानी हो जाएगी। देर-सबेर सभी टैक्सपेयर्स को नई टैक्स व्यवस्था में आना ही पड़ेगा। इससे पहले नई टैक्स व्यवस्था के तहत 7.75 लाख रुपये तक की आमदनी पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होता था जिससे यह बहुत ज्यादा आकर्षक नहीं थी क्योंकि तब पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत हर तरीके के निवेश और छूट प्रावधानों से 10 लाख रुपये तक की आमदनी टैक्स मुक्त हो जाया करती थी। नई व्यवस्था में तो यह सीमा ही बढ़कर 12 लाख रुपये हो गई है। साथ ही, नई व्यवस्था में टैक्स स्लैब भी पुरानी के मुकाबले ज्यादा है। इसलिए पुरानी व्यवस्था में बने रहने का अब कोई मतलब नहीं रह गया है। नई टैक्स व्यवस्था के लिए टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया गया है।

वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में 5 लाख रुपये की एकमुश्त छूट की घोषणा के पीछे सरकार की मंशा मध्य वर्ग को राहत देना तो है ही, अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ाने के लिए उपभोक्ता मांग में तेजी लाना भी है। पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से विकास दर में कमी आई है उसकी बड़ी वजह मांग में कमी है। मांग में कमी के पीछे महंगाई एक बड़ा कारण है। इनकम टैक्स में बड़ी राहत से लोगों की जेब में पैसा बचेगा जिससे खपत बढ़ेगी। खपत बढ़ेगी तो मांग में तेजी आएगी और मांग में तेजी आएगी तो कंपनियों का उत्पादन ज्यादा होगा। कंपनियों का उत्पादन ज्यादा होगा तो वह सरकार को ज्यादा टैक्स देंगे। उपभोक्ता खपत से भी सरकार का जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा। कहा जा रहा है कि इनकम टैक्स में बड़ी छूट से सरकारी खजाने को करीब 1 लाख करोड़ रुपये की चपत लगेगी। मगर इसका दूसरा पहलू यह भी है कि खपत और मांग बढ़ने से टैक्स के रूप में इसमें से ज्यादातर राशि वापस सरकारी खजाने में आ जाएगी।

वरिष्ठ नागरिकों को छूट

बजट में वरिष्ठ नागरिकों को भी राहत दी गई है। उनके लिए ब्याज पर टैक्स कटौती (टीडीएस) की सीमा को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। इसी प्रकार, किराये पर टीडीएस के लिए वार्षिक सीमा 2.40 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये किए जाने का प्रस्ताव है। इससे टीडीएस देयता वाले लेन-देनों की संख्या में कमी आएगी और कम भुगतान पाने वाले छोटे टैक्स पेयर्स लाभान्वित होंगे। टीसीएस की सीमा को 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही टीसीएस प्रावधानों के लिए भुगतान में विलंब को गैर-आपराधिक बनाने की घोषणा बजट में की गई है।■

INCOME TAX RETURN
INCOME TAX RETURN
INCOME TAX RETURN

नई व्यवस्था का नया टैक्स स्लैब

☐ 0-4 लाख रुपये- शून्य
☐ 4-8 लाख रुपये- 5%
☐ 8-12 लाख रुपये- 10%
☐ 12-16 लाख रुपये- 15%
☐ 16-20 लाख रुपये- 20%
☐ 20-24 लाख रुपये- 25%
☐ 24 लाख रुपये से ज्यादा- 30%

कृषि बनेगा विकास का पहला इंजन

सुरेंद्र प्रसाद सिंह

पीएम धन धान्य योजना होगी शुरू, कम उत्पादकता वाले 100 पिछड़े जिले होंगे शामिल

ब्याज सब्सिडी वाले केसीसी लोन का दायरा 3 लाख से बढ़कर हुआ 5 लाख रुपया

बिहार में बनेगा मखाना बोर्ड, तूर, उड़द व मसूर में आत्मनिर्भरता के लिए छह वर्षीय मिशन

केंद्र सरकार ने कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्र को देश के विकास का पहला इंजन मानते हुए आम बजट में इसे प्राथमिकता दी है। भारत की विकास संभावनाओं और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए कृषि को और प्रोत्साहन की आवश्यकता है। संसद में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि राज्यों की भागीदारी के साथ प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना शुरू की जाएगी। इस समग्र योजना के तहत फसलों की उत्पादकता वृधि से उत्पादन बढ़ाने, फसलों में विविधता (डाइवर्सिफिकेशन) अपनाने, फसल कटाई के बाद (पोस्ट हार्वेस्टिंग) भंडारण बढ़ाने, सिंचाई की सुविधाओं में सुधार करने, दीर्घ-अवधि और लघु-अवधि ऋण की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर दिया जाएगा।

पीएम धन धान्य योजना

प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में देश के 100 सबसे पिछड़े जिलों को शामिल किया जाएगा। इन जिलों में उत्पादकता कम है। इस योजना के माध्यम से वहां पर उत्पादकता बढ़ाने, खेती में विविधता लाने, सिंचाई और उपज के बाद भंडारण की क्षमता को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे। इसके तहत 1.7 करोड़ किसानों को मदद दी जाएगी। इन जिलों में फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन चालू किया जाएगा, जिससे उच्च पैदावार, कीट प्रतिरोध और जलवायु अनुकूलन के गुणों से संपन्न बीजों का लक्षित विकास व प्रचार किया जाएगा। इसके अलावा पांच वर्षीय कपास

उत्पादकता मिशन शुरू किया जाएगा, जिससे उच्च क्वालिटी व लंबे रेशे वाले कपास का उत्पादन हो सकेगा।

बिहार में मखाना बोर्ड

देश और विदेश में मखाना की बढ़ती मांग को देखते हुए वित्त मंत्री ने बजट में बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया है। इसके तहत मखाना उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्द्धन और विपणन में सुधार और किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) का गठन किया जाएगा। इससे मखाना किसानों और व्यापारियों को फायदा मिलेगा। बिहार के दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर जिले में मखाना की सबसे ज्यादा खेती होती है। देश के कुल मखाना उत्पादन का करीब 90 फीसदी उत्पादन इन्हीं जिलों में होता है। मखाना बोर्ड का गठन होने के बाद निर्यात में तेजी से बढ़ोतरी होगी और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। साथ ही युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।

केसीसी की सीमा बढ़ी

लघु व सीमांत किसानों को सस्ते व कृषि ऋण उपलब्ध कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से ब्याज सब्सिडी वाले ऋण की सीमा को तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया गया है। किसानों के लिए यह बड़ी राहत है, जिससे उन्हें साहूकारों से ऋण लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देश के 7.7 करोड़ किसानों, डेयरी संचालकों, पशुपालकों और मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड के मार्फत रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके तहत समय पर कर्ज का भुगतान करने वाले केसीसी धारकों को ब्याज पर 3 प्रतिशत की सब्सिडी मिलती है। इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जनवरी, 2025 से बिना गारंटी वाले केसीसी लोन को 1.60 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया था।

फलों-सब्जियों के लिए व्यापक योजना

वित्त मंत्री ने आम बजट में बागवानी फसलों के लिए व्यापक कार्यक्रम की घोषणा की है। इसके तहत सब्जियों और फलों के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की जा रही है जिससे उत्पादन, प्रोसेसिंग और निर्यात पर जोर दिया जाएगा। कृषि और इससे सम्बद्ध गतिविधियों को व्यापक स्तर पर प्रोत्साहन देने के लिए इसमें अन्य उपायों के साथ कपास उत्पादकता के लिए एक पांच वर्षीय अभियान और उच्च पैदावार करने वाले बीजों के लिए राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं।

तूर, उड़द व मसूर में आत्मनिर्भरता

देश की खाद्य सुरक्षा को महफूज रखने के लिए निर्मला सीतारमण ने आम बजट में दलहन उत्पादन में वृद्धि के लिए अरहर (तूर), उड़द और मसूर पर विशेष फोकस करने का प्रावधान किया है। दालों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार एक छह वर्षीय अभियान का शुभारंभ करेगी। सरकार की सहकारी क्षेत्र की केंद्रीय एजेंसियां (नेफेड और एनसीसीएफ) अगले चार वर्षों के दौरान किसानों से मिलने वाली इन तीन दालों को अधिकतम स्तर पर खरीदने को तैयार रहेगी।

मछुआरों का बदलेगा जीवन

मत्स्य व जलीय क्षेत्र की संभावनाओं को देखते हुए विशेष योजना शुरू की जाएगी। इससे समुद्र तटीय क्षेत्र के मछुआरों के जीवन में बदलाव आएगा। भारत समुद्री उत्पादों का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। इसे और मजबूत बनाने और वैश्विक बाजार में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए आम बजट में विशेष प्रावधान किया गया है।

इनके अलावा, यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए असम में यूरिया प्लांट शुरू करने की घोषणा की गई है। इसकी क्षमता 12.78 लाख टन सालाना होगी। खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाने की भी वकालत की गई है।■

वित्त मंत्री ने बजट में बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया है। इसके तहत मखाना उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्द्धन और विपणन में सुधार और किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) का गठन किया जाएगा। इससे मखाना किसानों और व्यापारियों को फायदा मिलेगा। बिहार के दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर जिले में मखाना की सबसे ज्यादा खेती होती है।

सहकारिता में मज

राजीव शर्मा

कार्यकारी निदेशक, एनसीयूआई

> ‘सहकारिता में सहकार’ सहकारिता के सात प्रमुख सिद्धांतों में शामिल है, जिसको आईसीए द्वारा भी रेखांकित किया गया है। सहकारिता का यह सिद्धांत इस बात को दर्शाता है कि सहकारी समितियों को क्षेत्रीय, स्थानीय और अंतरदेशीय स्तर पर एक साथ मिलकर काम करना है, जिससे सही मायने में सहकारिता आंदोलन को मजबूती मिलेगी।

नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम देश में पहली बार आयोजित हुए वैश्विक सहकारी सम्मेलन का साक्षी बना। देश के लिए यह गौरव की बात थी। 107 देश के सहकार प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में शिरकत की, जिसका आयोजन अंतरराष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन (आईसीए) और इफको के सौजन्य से किया गया। सहकारिता को लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शी नीति और देश के पहले सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा सहकारिता के क्षेत्र में शुरु की गई महत्वपूर्ण पहलों के बिना यह संभव नहीं था। केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह ने पहली बार ‘सहकारिता में सहकार’ की दृष्टिकोण को समझा और कहा कि सहकारी समितियों के बीच सामंजस्य को बनाए रखने के लिए समितियों के बीच सहकार की भावना का होना जरूरी है।

‘सहकारिता में सहकार’ सहकारिता के सात प्रमुख सिद्धांतों में शामिल है, जिसको आईसीए द्वारा भी रेखांकित किया गया है। सहकारिता का यह सिद्धांत इस बात को दर्शाता है कि सहकारी समितियों को क्षेत्रीय, स्थानीय और अंतरदेशीय स्तर पर एक साथ मिलकर काम करना है, जिससे सही मायने में सहकारिता आंदोलन को मजबूती मिलेगी। एक साथ मिलकर काम करने का फायदा यह होगा कि सहकारी समितियां संसाधनों, जानकारियों, नेटवर्क का साझा प्रयोग कर सकेंगी जिससे सभी की सामूहिक तरक्की होगी। ‘सहकारिता में सहकार’ का सबसे अहम फायदा यह है कि यह उत्पादन की मात्रा को बढ़ा सकता है। सामूहिक प्रयासों के परिणाम अधिक कारगर और व्यापक होते हैं। कोई भी सहकारी समिति जो अकेले अधिक उत्पादन करने में सक्षम नहीं होती, ‘सहकारिता में सहकार’ की अवधारणा को अपनाकर अपने उत्पादन को कई गुना बढ़ा सकती हैं।

संसाधनों का प्रयोग भी इसी सिद्धांत के माध्यम से हो सकता है। सहकारिता के माध्यम से सहकारी समितियां अपने संसाधनों का सामूहिक प्रयोग कर सकती हैं। सामूहिक प्रयास से मिलने वाले लाभ भी अधिक होंगे, जिसका सामूहिक रूप से वितरण किया जा सकता है। इस लिहाज से ‘सहकारिता में सहकार’ की अवधारणा को अपना कर समूह के सदस्यों की आजीविका को बेहतर किया जा सकता है। बाजार तक पहुंच भी ‘सहकारिता में सहकार’ के माध्यम से ही बनाई जा सकती है। छोटे या कम सदस्यों के समूह के बीच किए गए उत्पादन को हमेशा बड़ा बाजार हासिल करना मुश्किल होता है, जबकि समूह के साथ किए गए काम से अधिक व्यापक बाजारों तक पहुंच बनाई जा सकती है, जिससे उत्पादन का उचित मूल्य प्राप्त किया जा सकता है। फेडरेशन व बड़ी सहकारिता

बूत होता सहकार

समितियों के साथ साझेदारी एक बड़े बाजार का रास्ता खोल सकती है। उदाहरण के लिए कृषि से जुड़ी सहकारी समितियां बड़े नेटवर्क के साथ साझेदारी करके अपने उत्पादन के साथ ही मांग को भी बढ़ा सकती हैं, जिससे सहकारी समितियों को स्थानीय बाजार के साथ ही अंतरराष्ट्रीय बाजार भी उपलब्ध हो सकेगा।

'सहकारिता में सहकार' के सिद्धांत से ही सहकारिता की सही नीतियों को अपनाए जाने के लिए आवाज उठाई जा सकती है। अधिक सदस्यों की संख्या वाली सहकारी समितियों की बात नीति निर्धारण के समय भी रखी जाती है। समितियों के प्रतिनिधि बड़ी समितियों में प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए सहकारी समितियों की समस्या के निराकरण के लिए बेहतर तरीके से आवाज बुलंद की जा सकती है। समूह के बीच काम करने का एक अन्य लाभ यह भी है कि प्रशिक्षण व तकनीकी दक्षता का फायदा सभी लोग उठा सकते हैं। सहकारी समितियों को तकनीक की जानकारी देने के लिए एनसीयूआई के एनसीडीसी द्वारा समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। प्रशिक्षण का प्रयोग सहकारी संगठनों के संचालन में करने से उसका सीधा फायदा उत्पादन और सहकारी समितियों की तरक्की के रूप में मिलता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सहकारी समितियों के बीच सहकारिता के सिद्धांत को लागू करने से लाभ को अधिकतम किया जा सकता है।

अब प्रश्न यह उठता है कि सहकारी समितियों के बीच सहकारिता के सिद्धांत को किस तरह मजबूत किया जाए। इसके लिए सहकारी समितियों के बीच नेटवर्क व साझेदारी को मजबूत करना होगा। एक ही क्षेत्र में काम करने वाली समितियां या एक भी क्षेत्र में काम करने वाले सहकारी संगठन आपस में मिलकर अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। इसके लिए सामूहिक रूप से मार्केटिंग अभियान चलाए जा सकते हैं, जिसके माध्यम से सहकारी समितियों द्वारा बनाए गए उत्पादों को एक ब्रांड के रूप में स्थापित करने में सहायता मिल सकती है। सामूहिक मार्केटिंग योजना का फायदा यह होगा कि अधिक से अधिक लोगों तक सहकारिता के अहम प्रयोगों को आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। ज्वाइंट वेंचर या फिर संयुक्त उपक्रमों के गठन से भी 'सहकारिता में सहकार' को बढ़ावा दिया जा सकता है।

नवंबर 2024 में आयोजित तीन दिवसीय वैश्विक सहकारिता सम्मेलन में सहकारिता के विभिन्न पहलुओं के साथ इस सिद्धांत को व्यवहारिक रूप से लागू करने पर विस्तृत चर्चा की गई जिसका विश्व भर के प्रतिनिधियों ने समर्थन किया। निश्चित रूप से 'सहकारिता में सहकार' की यह अपील दूर तक जाएगी।■

> **प्रश्न यह उठता है कि सहकारी समितियों के बीच सहकारिता के सिद्धांत को किस तरह मजबूत किया जाए। इसके लिए सहकारी समितियों के बीच नेटवर्क व साझेदारी को मजबूत करना होगा। एक ही क्षेत्र में काम करने वाली समितियां या एक भी क्षेत्र में काम करने वाले सहकारी संगठन आपस में मिलकर अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं।**

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के कार्यक्रमों का उद्घाटन

युवाओं को प्रशिक्षण पर फोकस

HOT PLATE
GNETIC STIRRER

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारिता वर्ष के दौरान आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा का किया शुभारंभ

युवाओं में जनजागरण अभियान और उन्हें प्रशिक्षित करने पर होगा जोर, भारतीय सहकारिता की दुनिया में पैठ होगी मजबूत

युवा सहकार टीम

नए वर्ष की शुरूआत के साथ ही वैश्विक सहकारिता महोत्सव 'अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष' के विभिन्न आयोजनों का प्रारंभ हो चुका है। भारत ने भी पूरे साल सहकारिता से संबंधित आयोजन किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा (कैलेंडर) तैयार की है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पिछले महीने मुंबई में आयोजित एक समारोह में इसका शुभारंभ करते हुए बताया कि सहकारिता मंत्रालय ने भारत में सहकारिता वर्ष मनाने के लिए 12 माह का एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया है। भारत में सहकारिता वर्ष इस तरह से मनाया जाएगा जिससे सहकारिता की धाक देशव्यापी होगी। इस दौरान सहकारिता के विस्तार, इस क्षेत्र में शुचिता लाने, सहकारी संस्थाओं को समृद्ध बनाने, कई नए क्षेत्रों में सहकारिता की पहुंच बढ़ाने और भारत के हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार से सहकारिता से जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ने के प्रयास किए जाएंगे।

युवा जागृति अभियान

सहकारिता के लिए यह वर्ष महत्वपूर्ण बदलावों वाला साबित होगा। इस दौरान सहकारिता के प्रति युवाओं को जागृत करने के लिए अभियान चलेगा और उन्हें प्रशिक्षण देने पर जोर होगा। सहकारिता में सुशासन और स्थिरता को प्रोत्साहन दिया जाएगा। साथ ही, सहकारिता मंत्रालय की विभिन्न पहलों को लागू करने के अभियान को तेज करने और वैश्विक स्तर पर भारतीय सहकारिता की पैठ मजबूत बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के दौरान घरेलू पैक्स से लेकर अपेक्स (शीर्ष) सहकारी संस्थाओं को सशक्त किया जाएगा।

केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि 31 दिसंबर, 2025 को जब अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष समाप्त होगा, तब तक भारतीय सहकारिता का विकास सिमेट्रिक और समावेशी होगा और ‘सहकार से समृद्धि’ के सरकार के लक्ष्य को काफी हद तक प्राप्त कर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति और 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति में सहकारिता क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान होगा। सहकारिता क्षेत्र सामाजिक समरसता, समानता और समावेशिता के सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ेगा।

सहकारी शिक्षा और शोध को बढ़ावा

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के दौरान राज्यों के सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने, सहकारिता के नए क्षेत्रों को बढ़ावा देने के साथ ही सहकारी शिक्षा और शोध को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इस वैश्विक अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाने तथा सर्वाधिक प्रभावी तरीकों की पहचान करने के लिए मंत्रालय में नियमित रूप से उच्च स्तरीय बैठकें हो रही हैं। इसके लिए बनाई गई नेशनल कोऑपरेटिव कमेटी (एनसीसी) की बैठक में अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा तैयार किए गए लोगो का प्रयोग मानकों के तहत करने का निश्चय किया गया। इसके अलावा, राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति और राज्य शीर्ष समिति का गठन किया गया है जो पूरे वर्ष सहकारिता क्षेत्र में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का संचालन करेगी। सहकारिता क्षेत्र में पूरे वर्ष आयोजित होने वाली गतिविधियों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया जाएगा। स्थानीय स्तर पर सेमिनार और वर्कशाप का आयोजन किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा किए गए आयोजनों के साथ भारतीय सहकारी संगठनों के आयोजनों का तालमेल किया जाएगा।

पूरे वर्ष प्रस्तावित आयोजन

- **ग्रामीण स्तर पर पैक्स की बोर्ड बैठकें**
- **लेखांकन एवं लेखा प्रशिक्षण**
- **सदस्यता अभियान मॉडल एवं सहकारी समितियों का गठन**
- **किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से प्रशिक्षण और प्रदर्शनियों का आयोजन**

गांवों में मजबूत होगी सहकारिता

ग्रामीण स्तर पर सहकारी संगठनों को पैक्स के माध्यम से मजबूत करने और स्वयं सेवी संगठनों को सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया जाएगा। देश के आर्थिक सामजिक ढांचे को मजबूत करने में सहकारिता की भूमिका सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाएगा। सहकारिता में महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने और महिला नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा दिया जाएगा। युवाओं, महिलाओं और विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। कार्यक्रमों का संचालन चार स्तर पर होगा। ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक सहकारी समितियां और पैक्स कार्य करेंगी। राज्य व जिला स्तर पर राज्य सहकारी दुग्ध सहकारी संघ, जिला सहकारी बैंक मुख्य भूमिका निभाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर मंत्रालय और मल्टी स्टेट सहकारी समितियां विभिन्न आयोजन करेंगी। प्रशिक्षण केंद्र भी इन कार्यक्रमों में बड़ी भूमिका निभाएंगे। इस दौरान मल्टी परपज पैक्स के लिए हैंड होल्डिंग और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सोशल मीडिया से लेकर मुख्य धारा की मीडिया के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा।

सहकारिता क्षेत्र में पूरे वर्ष आयोजित होने वाली गतिविधियों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया जाएगा। स्थानीय स्तर पर सेमिनार और वर्कशाप का आयोजन किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा किए गए आयोजनों के साथ भारतीय सहकारी संगठनों के आयोजनों का तालमेल किया जाएगा।

> **भारतीय सहकारिता क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के प्रयास से 55 नई पहलों की शुरूआत की गई है, जिस पर सहकारी संस्थाएं लगातार आगे बढ़ रही हैं। इसमें सबसे पहले प्राथमिक सहकारी समितियों (पैक्स) को मजबूत बनाने के लिए वहां मॉडल बायलॉज लागू कर दिए गए हैं।**

सहकारिता के माध्यम से युवाओं के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम, उद्यमशीलता विकास, प्रशिक्षण और डिजिटल पहलों से भारतीय सहकारिता लगातार मजबूत हो रही है। देश की प्रमुख सहकारी संस्थाओं के साथ-साथ नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी (एनवाईसीएस) जैसी युवा केंद्रित सहकारी संस्थाओं की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नीतिगत साझेदारी से सहकारिता में शिक्षा, शोध और अन्य सहकारी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारतीय सहकारिता क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के प्रयास से 55 नई पहलों की शुरूआत की गई है, जिस पर सहकारी संस्थाएं लगातार आगे बढ़ रही हैं। इसमें सबसे पहले प्राथमिक सहकारी समितियों (पैक्स) को मजबूत बनाने के लिए वहां मॉडल बायलॉज लागू कर दिए गए हैं। तीन बड़ी बहु राज्य समिति एनसीईएल, बीबीएसएसएल और एनसीओएल को शुरू किया गया है। सहकारिता से जुड़े विभिन्न संस्थाओं के कारोबार को सहज और लाभप्रद बनाने के लिए समितियों को आयकर में छूट दी गई है। सहकारी चीनी मिलों में सुधार की प्रक्रिया, सहकारी बैंको की कार्यप्रणाली में सुधार और एनसीडीसी की गतिविधियों को विस्तार दिया गया है। जेम पोर्टल के माध्यम से सहकारी क्षेत्रों के उत्पादों को विस्तृत बाजार देने की महत्वपूर्ण पहल की गई है। इन प्रयासों का उद्देश्य सहकारिता क्षेत्र में विविधता और इसके प्रभावों को बढ़ावा देना है।

वर्ष 2024 में भारत ने वैश्विक सहकारिता सम्मेलन की अगुवाई की थी। इसी दौरान अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का बिगुल फूंका गया। सहकारिता के वैश्विक सम्मेलन के आयोजन से विश्व भर में भारत का दर्जा ऊंचा हुआ है। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष भारत के सहकारी आंदोलन को वैश्विक स्तर पर व्यापक रूप से प्रदर्शित करने का सुनहरा अवसर है।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित करने के बाद से ही सहकारिता मंत्रालय ने इस वर्ष को सफलतपूर्वक आयोजित करने की तैयारी पूरी कर ली। पूरे वर्ष चलने वाले आयोजनों व कार्यक्रमों के दौरान सहकारी संस्थाओं की प्रगति और उपलब्धियों का दस्तावेजीकरण किया जाएगा। साल के अंत में एक समग्र रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसमें सहकारी आंदोलन की सफलता, अनुभव और प्रभाव का उल्लेख किया जाएगा। इसी रिपोर्ट के आधार पर 2026 के लिए बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा जिसे संयुक्त राष्ट्र को सौंपा जाएगा।■

कोऑपरेटिव बैंकों में मिलेंगी सभी सेवाएं

युवा सहकार टीम

Cooperative Banks

अगले तीन साल में सामान्य बैंकों की तरह ग्राहकों को मिलने लगेंगी सभी सुविधाएं

राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम सहकारी बैंकों का है अंब्रेला संगठन

कोऑपरेटिव बैंकों को मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने इन बैंकों को राष्ट्रीय और निजी बैंकों की तरह ग्राहकों को सभी तरह की सेवाएं देने से लैस करने का फैसला किया है। अगले तीन साल में ये बैंक इन सेवाओं से युक्त हो जाएंगे। सेवाओं का विस्तार होगा तो इन बैंकों का भी विस्तार होगा। बैंकों का विस्तार होगा तो रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे। कोऑपरेटिव बैंकों की स्थिति में सुधार लाने के लिए एक अंब्रेला संगठन राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम (एनयूसीएफडीसी) बनाया गया है जो एक नियामक की तरह काम करेगा। एनयूसीएफडीसी के मुंबई स्थित कॉरपोरेट कार्यालय का केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पिछले महीने उद्घाटन किया।

इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि सभी शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक अगले तीन साल में राष्ट्रीय बैंकों और निजी बैंकों द्वारा दी जाने वाली सभी सेवाओं से युक्त हो जाएंगे जिनसे इनकी सेवाओं का विस्तार होगा। डिजिटल बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन लेनदेन और विदेश के साथ व्यापार जैसी गतिविधियों को अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के साथ समाहित करने का काम 'अंब्रेला संगठन' करेगा। इसके साथ-साथ संसाधनों का बेहतर उपयोग, बैंकिंग प्रक्रिया में सुधार और सभी कोऑपरेटिव बैंकों के अकाउंटिंग सिस्टम को एक करना इसका लक्ष्य रहेगा।

इस समय देश में कुल 1,465 शहरी सहकारी बैंक हैं, जिनमें से लगभग आधे गुजरात और महाराष्ट्र में हैं। देश में 49 शेड्यूल्ड बैंक हैं और 8.25 लाख से अधिक सहकारी संस्थाएं हैं। अमित शाह ने कहा कि आने वाले दिनों में पूरे देश में 'सहकारिता में सहकार' के सिद्धांत को लागू किया जाएगा। इसके तहत कोऑपरेटिव संस्थाओं का सारा लेनदेन और वित्तीय व्यवहार कोऑपरेटिव बैंकों के माध्यम से ही होगा। 'सहकारिता में सहकार' के सिद्धांत को देश के सभी राज्यों में जमीन पर उतारने से ही सहकारिता क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के कई सारे मुद्दे भारतीय रिजर्व बैंक के साथ सुलझाए हैं। आने वाले दिनों में अंब्रेला संगठन को मजबूत कर हम विश्वास और व्यापार को बढ़ाएंगे और सभी अड़चनों को दूर करेंगे।

एमपैक्स का प्रशिक्षण कार्यक्रम

24 जनवरी को आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह ने सहकारिता के नए बायलॉज से बनी 10 हजार बहुद्देश्यीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (एमपैक्स) का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किया। इसे नई शुरूआत बताते हुए सहकारिता मंत्री ने कहा कि देश की हर पंचायत में एक पैक्स की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। पैक्स को व्यवहारिक बनाने के लिए मॉडल बायलॉज बनाए गए जिसे सभी राज्यों ने स्वीकार किया है। मोदी सरकार ने 2,500 करोड़ रुपये खर्च कर हर पैक्स को कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर दिए हैं और कई प्रकार की नई गतिविधियों को पैक्स के साथ जोड़ने का प्रयास किया है।■

> **सभी शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक अगले तीन साल में राष्ट्रीय बैंकों और निजी बैंकों द्वारा दी जाने वाली सभी सेवाओं से युक्त हो जाएंगे जिनसे इनकी सेवाओं का विस्तार होगा। डिजिटल बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन लेनदेन और विदेश के साथ व्यापार जैसी गतिविधियों को अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के साथ समाहित करने का काम 'अंब्रेला संगठन' करेगा।**

इनोवेशन आधारित होंगी भविष्य की नौकरियां

NYCS
युवा सहकार
www.nycsindia.com
जनवरी 2025, नई दिल्ली
युवाओं को रोजगार
लीक से हटकर अवसर बनाने की कोशिश
अंदर के पन्नों पर:
10 हजार नए एम-पैक्स का शुभारंभ
पुणे पुस्तक महोत्सव में बने पांच गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड

युवा सहकार टीम

परंपरागत क्षेत्रों की नौकरियों, चाहे वह सरकारी क्षेत्र हो या फिर निजी क्षेत्र, में हाल के वर्षों में काफी कमी आई है। दूसरी तरफ, रोजगार के नए-नए क्षेत्र उभर रहे हैं जिनमें काफी संख्या में युवाओं को अवसर मिल रहे हैं। हरित रोजगार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, आतिथ्य एवं पर्यटन और स्वास्थ्य सेवा जैसे उभरते क्षेत्र रोजगार इकोसिस्टम को नया स्वरूप दे रहे हैं। साथ ही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, डिजिटल कॉमर्स, साइबर सुरक्षा, ब्लॉकचेन जैसी तकनीक संचालित नौकरियों का बाजार लगातार बढ़ रहा है। जैसे-जैसे इनका दायरा बढ़ता जाएगा इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ते जाएंगे। इसे देखते हुए सरकार भी नवाचार को प्रोत्साहन देकर उत्पादकता में वृद्धि और भविष्य के कार्यबल के लिए युवाओं को तैयार कर रही है।

युवाओं में इसे लेकर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्रालय ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के सहयोग से 'भविष्य की नौकरियों' पर हाल ही में एक सम्मेलन का आयोजन किया। इसका विषय 'भविष्य के कार्यबल को स्वरूप देना: गतिशील दुनिया में विकास को गति देना' था। इसमें नीति निमार्ताओं, उद्योग जगत के प्रमुख व्यक्तियों और विशेषज्ञों ने उभरते रोजगार परिदृश्य और भारत में भविष्य के लिए तैयार कार्यबल के लिए रणनीति तैयार करने पर अपने विचार रखे। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने इस मौके पर कहा, 'शिक्षा और रोजगार में समन्वय के लिए कौशल विकास सरकार के प्रयासों के केंद्र में है। इसके माध्यम से नवाचार को प्रोत्साहन देकर, उत्पादकता में वृद्धि कर और कार्यबल के लिए व्यक्तियों को तैयार कर सरकार रोजगार सृजित कर रही है। साथ ही, वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) का निर्माण किया जा रहा है।' उन्होंने कौशल और मानकों की पारस्परिक मान्यता जैसी पहलों के माध्यम से वैश्विक कार्यबल की कमी को

दूर करने की भारत की क्षमता पर भी प्रकाश डाला। सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के नए तौर-तरीकों पर फोकस (देखें : युवा सहकार जनवरी 2025) कर रही है।

तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में सफल होने के लिए भारत के समक्ष तीन प्रमुख प्रश्न उभरे हैं। पहला, तकनीक संचालित नौकरी बाजार में तेजी से आगे बढ़ने के लिए सुसज्जित डिजिटल रूप से कुशल कार्यबल कैसे विकसित करें? दूसरा, समावेशी कार्यबल बनाने के लिए कौन सी रणनीति अपना सकते हैं जहां विविधता को महत्व दिया जाता है और सभी को समान अवसर दिए जाते हैं? तीसरा, हम अपने कार्यबल संस्कृति में पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं और मूल्यों को कैसे एकीकृत कर सकते हैं? केंद्रीय श्रम एवं रोजगार सचिव सुमिता डावरा ने इन सवालों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवा, विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स और हरित नौकरियों जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिए कुशल और अनुकूलनीय कार्यबल महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने 'विश्व की जीसीसी राजधानी' के रूप में भारत की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 1,700 वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) 20 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दे रहे हैं। यह संख्या वर्ष 2030 तक उल्लेखनीय रूप से बढ़ने का अनुमान है। ये जीसीसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, डिजिटल कॉमर्स, साइबर सुरक्षा, ब्लॉकचेन, संवर्धित वास्तविकता और आभासी वास्तविकता जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों को अपना रहे हैं। यह भारत की असाधारण तकनीकी प्रतिभा का प्रमाण है।

हरित रोजगार: भारत 2023 में 10 लाख नौकरियों के साथ अक्षय ऊर्जा रोजगार में विश्व में चौथे स्थान पर था। सुजलॉन ग्रुप के सीएचआरओ राजेंद्र मेहता ने कहा, 'स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन से 2030 तक वैश्विक स्तर पर 10.3 लाख नई नौकरियां सृजित होंगी, जो 500 गीगावॉट गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य से प्रेरित है। इनमें अक्षय ऊर्जा तकनीशियन, स्थिरता सलाहकार, पर्यावरण इंजीनियर, हरित भवन पेशेवर और कार्बन बाजार विश्लेषक शामिल हैं, जो एक स्थायी, ऊर्जा-कुशल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करते हैं।'

आतिथ्य एवं पर्यटन: इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के मानव संसाधन उपाध्यक्ष अजय दत्ता ने कहा कि पर्यटन उद्योग महामारी के बाद फिर से उभर रहा है। विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ पर्यटन उद्योग का लक्ष्य 2047 तक 3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचना है। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होगा। उन्होंने सरकार से आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने का आग्रह किया।

इनके अलावा, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स आदि ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें भविष्य में नौकरियों के अवसर बढ़ने की पूरी संभावना है। गतिशील वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भारत के कार्यबल को तैयार करने के लिए सम्मेलन में कार्यान्वयन योग्य नीतिगत सिफारिशें की गईं। इनमें कौशल विकास और तकनीकी उन्नयन को बढ़ावा देना, समावेशी विकास के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना, डिजिटल साक्षरता और पर्यावरण अनुकूल कार्यबल मूल्यों को बढ़ावा देना और कार्यबल विकास में समावेशिता और स्थिरता को प्राथमिकता देना शामिल है। इन प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान देकर भारत भविष्य के लिए तैयार कार्यबल का निर्माण करेगा। यह न केवल घरेलू मांगों को पूरा करेगा, बल्कि वैश्विक कार्यबल चुनौतियों का भी समाधान करेगा।■

मैन्युफैक्चरिंग

इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पर सीआईआई राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष और डेकी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक विनोद शर्मा ने उद्योग, सरकार और कार्यबल को भविष्य के लिए तैयार करने की चुनौतियों और समाधानों की पहचान करने के लिए एक समर्पित 'नौकरियों के भविष्य पर कार्यबल' बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने कौशल बढ़ाने और अधिक अनुकूलनीय कार्यबल बनाने के लिए अप्रेंटिसशिप और कमाओ और सीखो कार्यक्रमों में निवेश बढ़ाने का आग्रह किया।

तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में सफल होने के लिए भारत के समक्ष तीन प्रमुख प्रश्न उभरे हैं। पहला, तकनीक संचालित नौकरी बाजार में तेजी से आगे बढ़ने के लिए सुसज्जित डिजिटल रूप से कुशल कार्यबल कैसे विकसित करें? दूसरा, समावेशी कार्यबल बनाने के लिए कौन सी रणनीति अपना सकते हैं जहां विविधता को महत्व दिया जाता है और सभी को समान अवसर दिए जाते हैं? तीसरा, हम अपने कार्यबल संस्कृति में पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं और मूल्यों को कैसे एकीकृत कर सकते हैं?

एनसीएस पोर्टल से हर साल मिलेंगी 11 लाख नौकरियां

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने की निजी जॉब पोर्टल के साथ भागीदारी

समझौता ज्ञापन से नेशनल करियर सर्विस (एनसीएस) पोर्टल पर प्रति वर्ष 10 लाख घरेलू और 1.25 लाख विदेशी रिक्तियां आने की उम्मीद

युवा सहकार टीम

रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और देश-विदेश में नौकरी चाहने वाले युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने को केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है। इस दिशा में कदम उठाते हुए सरकार बजटीय समर्थन के अलावा प्रमुख निजी कंपनियों से समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर जोर दे रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने निजी क्षेत्र के प्रमुख नौकरी पोर्टल फाउंडइट (पूर्व में मोंस्टर) के साथ एक एमओयू किया है। इसका उद्देश्य नेशनल करियर सर्विस (एनसीएस) पोर्टल पर पंजीकृत नौकरी चाहने वाले लोगों के लिए अंतरराष्ट्रीय एवं घरेलू रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है। इसके माध्यम से हर साल देश और विदेश में 11 लाख से ज्यादा नौकरियों के अवसर प्राप्त होंगे।

इस एमओयू से एनसीएस पोर्टल पर पंजीकृत नौकरी खोजने वालों को न केवल भारत में, बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य पूर्व में भी रिक्तियों तक पहुंच प्राप्त होगी। इससे उनके लिए रोजगार के अवसरों में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार और युवा

मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया की उपस्थिति में इस एमओयू पर हस्ताक्षर किये गए। मांडविया ने इस मौके पर एनसीएस पोर्टल की परिवर्तनकारी भूमिका को उजागर करते हुए कहा, 'भारत और विदेशों में नौकरी चाहने वाले लोगों और रोजगार के अवसरों के बीच की खाई को यह पोर्टल दूर करता है। यह नौकरी चाहने वाले लाखों लोगों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नियोक्ताओं के साथ जोड़ता है। प्रतिदिन 3,000 से 4,000 नौकरी के विज्ञापनों के साथ इस एमओयू के माध्यम से प्रति वर्ष एनसीएस में 1.25 लाख अंतरराष्ट्रीय रिक्तियां और 10 लाख से अधिक घरेलू रिक्तियां आने की उम्मीद है।'

ऐसे करेगा काम

फाउंडइट भारत, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों में भर्ती करने के लिए नियोक्ताओं से नौकरी की मांग इकट्ठा करेगा और एनसीएस के पोर्टल पर इन अवसरों को पोस्ट करेगा। एनसीएस पोर्टल पर नौकरी की सूचियां एपीआई के माध्यम से एकीकृत की जाएंगी। इससे नौकरी चाहने वाले लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। निष्पक्ष और समावेशी भर्ती प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए एनसीएस महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों जैसे कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों के लिए नौकरी के समान अवसर सुनिश्चित करने को प्रतिबद्ध है। इस समझौते के तहत फाउंडइट को एनसीएस पोर्टल के माध्यम से महिलाओं एवं दिव्यांगजनों सहित एक बड़े और विविध उम्मीदवारों के पूल तक पहुंच प्राप्त होगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय इसके लिए डेटाबेस एकीकरण की सुविधा प्रदान करेगा। इससे फाउंडइट एक सहज तकनीकी इंटरफेस के माध्यम से एक व्यापक प्रतिभा आधार से जुड़ेगा। यह ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यम के लिए सुलभ होगा।

40 लाख से अधिक नियोक्ताओं के पंजीकरण के साथ एनसीएस पोर्टल ने अपनी स्थापना के बाद से 4.40 करोड़ से अधिक रिक्तियों की भर्ती में मदद की है। एनसीएस पोर्टल के साथ ई-माइग्रेट प्लेटफॉर्म का एकीकरण किया गया है जिसके अंतर्गत विदेश मंत्रालय के साथ पंजीकृत 500 से अधिक सक्रिय भर्ती एजेंसियों को शामिल किया गया है। इससे विदेश में नौकरी चाहने वाले युवाओं को मदद मिल रही है। साथ ही, यह पोर्टल माय भारत, एसआईडीएच पोर्टल के साथ एकीकृत है जो युवाओं के बीच कौशल अंतर को पाटने में मदद करता है ताकि वे रोजगार प्राप्त करने के योग्य बन सकें।

श्रम मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा के मुताबिक, जर्मनी, फिनलैंड और मध्य पूर्व के देश ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर जॉब के लिए कुशल श्रमिकों की सक्रिय रूप से तलाश कर रहे हैं। इस समझौता ज्ञापन से एनसीएस को इन रिक्तियों को सुविधाजनक बनाने और नौकरी चाहने वाले भारतीयों के लिए करियर के अवसरों को बढ़ाने में मदद मिलेगी। फाउंडइट के सीईओ वी. सुरेश ने कहा कि यह साझेदारी मोदी सरकार के 'सबका साथ, सबका विकास' के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो समावेशी रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देती है। ■

इस एमओयू से एनसीएस पोर्टल पर पंजीकृत नौकरी खोजने वालों को न केवल भारत में, बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य पूर्व में भी रिक्तियों तक पहुंच प्राप्त होगी। इससे उनके लिए रोजगार के अवसरों में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी।

किताबों का कोई विकल्प नहीं

युवा सहकार टीम

वैश्विक भागीदारी के साथ इस बार की थीम ‘रिपब्लिक@75’ रखी गई और रूस फोकस राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ है। इस मेले में 50 से ज्यादा देशों ने भाग लिया और 2000 से ज्यादा प्रकाशकों ने अपने स्टॉल लगाए। इस दौरान कई किताबों का विमोचन हुआ और 1000 से ज्यादा लेखकों और वक्ताओं ने पाठकों से प्रत्यक्ष संवाद किए। मेले में 600 से ज्यादा साहित्यिक व सांस्कृतिक सत्र आयोजित किए गए।

नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में नौ दिन तक चले विश्व पुस्तक मेला 2025 में पहुंचे पुस्तक प्रेमियों की संख्या को देखते हुए यह बात दावे के साथ कही जा सकती है कि देश में अभी पुस्तकों के प्रति पाठकों का प्रेम कम नहीं हुआ है। डिजिटल बुक के बढ़ते चलन के इस दौर में फिजिकल बुक के प्रति लोगों का आकर्षण बना हुआ है, बशर्ते पाठकों को अच्छी सामग्री आसानी से और उचित कीमत पर उपलब्ध हों। 1 फरवरी को पुस्तक मेले का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी कहा कि किताबें पढ़ना सिर्फ शौक नहीं है, यह एक परिवर्तनकारी अनुभव है। विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों की किताबें पढ़ने से क्षेत्रों और समुदायों के बीच संबंध बेहतर बनते हैं। विश्व पुस्तक मेले का आयोजन नेशनल बुक ट्रस्ट की ओर से किया जाता है।

राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि पाठ्यक्रम की निर्धारित पुस्तकों को पढ़ने के अलावा स्कूली बच्चों को विभिन्न विषयों पर विभिन्न प्रकार की पुस्तकें पढ़नी चाहिए। इससे उन्हें अपनी क्षमता और योग्यताओं को पहचानने में मदद मिलेगी और वे अच्छे इंसान बनेंगे। हम अपने बच्चों में जो सबसे अच्छी आदत विकसित कर सकते हैं, वह है किताबें पढ़ने का शौक। हर बड़े को इसे एक महत्वपूर्ण कर्तव्य के रूप में लेना चाहिए।

नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रो. मिलिंद सुधाकर मराठे के मुताबिक, इस बार लोगों की संख्या पहले से अधिक रही। हालांकि, रिपोर्ट लिखे जाने तक आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं किए गए थे लेकिन मराठे का अनुमान है कि मेले में आने वाले पुस्तक प्रेमियों की संख्या 25 लाख को पार कर गई। पिछले साल की तुलना में लोगों की संख्या में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इससे यही पता चलता है कि भारत में पुस्तकें पढ़ने की आदत में कमी नहीं आई है। प्रकाशन बाजार भी 18 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। मेले में स्टॉल लगाने वाले प्रकाशकों ने पाया कि खरीदारों की साहित्यिक पसंद में विविधता थी, जिसमें गल्प कथा और गैर गल्प कथा से लेकर विज्ञान कथा और बच्चों की पुस्तकों तक सब कुछ शामिल हैं।

समर्थ युवा फाउंडेशन के अध्यक्ष राजेश

पांडे ने कहा, 'जैसे मिलना और हाथ पकड़ कर चलना जरूरी है, उसी तरह किताबों को पढ़ते समय उनका स्पर्श जरूरी है। इससे पाठक लेखक की कहानी से ज्यादा जुड़ पता है। अगर डिजिटल बुक इतनी ही प्रभावी होती तो पुस्तक मेलों का आयोजन ही क्यों किया जाता? पिछले साल दिसंबर में नेशनल बुक ट्रस्ट की ओर से आयोजित पुणे बुक फेस्टिवल में पांच गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। उसका संयोजक मैं ही था। फिजिकल बुक पढ़ना आज भी लोगों उतना ही पसंद है जितना पहले था। किताबों का कोई विकल्प नहीं है।' पुणे बुक फेस्टिवल ने विश्व पुस्तक मेले में भी अपना स्टॉल लगाया था।

एक से नौ फरवरी तक आयोजित इस मेले में साहित्य प्रेमी अपने पसंदीदा लेखकों की एक झलक पाने या अपनी पसंदीदा किताब की तलाश में उमड़ पड़े। वैश्विक भागीदारी के साथ इस बार की थीम 'रिपब्लिक@75' रखी गई और रूस फोकस राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ है। इस मेले में 50 से ज्यादा देशों ने भाग लिया और 2000 से ज्यादा प्रकाशकों ने अपने स्टॉल लगाए। इस दौरान सैकड़ों किताबों का विमोचन हुआ और 1000 से ज्यादा लेखकों और वक्ताओं ने पाठकों से प्रत्यक्ष संवाद किए। मेले में 600 से ज्यादा साहित्यिक व सांस्कृतिक सत्र आयोजित किए गए। इस दौरान विद्वान, शिक्षक, बच्चे, लेखक, प्रकाशक और पुस्तक प्रेमी एक छत के नीचे नजर आए।

राष्ट्रीय पुस्तक
NATIONAL BOO
nbt.india

पुस्तक मेले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पीएम युवा 2.0 योजना के तहत 41 पुस्तकों का विमोचन किया। उन्होंने उन 41 युवा लेखकों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी लेखनी और रचनात्मकता साहित्यिक परिदृश्य को समृद्ध करेगी और बौद्धिक विमर्श को एक नई दिशा प्रदान करेगी। उन्होंने उभरते लेखकों को मार्गदर्शन देने तथा उनका पोषण करने, भारतीय संस्कृति, विरासत, इतिहास, भाषाओं तथा साहित्य के गौरवशाली राजदूतों को बढ़ावा देने तथा स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों की कहानियों को प्रकाश में लाने पर जोर दिया। प्रधान ने इस बात पर भी जोर दिया कि देश भर में भारतीय भाषाओं में पुस्तकों को बढ़ावा देना एक राष्ट्रीय मिशन है। पीएम युवा जैसी पहल इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में 'भारतीय भाषा पुस्तक योजना' की घोषणा की गई है जो इस राष्ट्रीय प्रयास को गति प्रदान करेगी।■

वैश्विक भागीदारी के साथ इस बार की थीम 'रिपब्लिक@75' रखी गई और रूस फोकस राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ है। इस मेले में 50 से ज्यादा देशों ने भाग लिया और 2000 से ज्यादा प्रकाशकों ने अपने स्टॉल लगाए।

विकास, नवाचार और युवा सशक्तिकरण को बढ़ावा

> एनवाईसीएस के समर्थन से समीर जाधव और भी बड़ी सफलता हासिल करने के लिए तैयार हैं। युवा सशक्तिकरण के तहत उद्यमशीलता और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने से युवाओं की व्यावसायिक और विकास क्षमता में वृद्धि हो रही है।

युवा सहकार टीम

नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड (एनवाईसीएस) युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने, उन्हें सशक्त बनाने और आर्थिक रूप से उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी ध्येय को आगे बढ़ाते हुए युवाओं के इस सहकारी संगठन के दिल्ली स्थित प्रधान कार्यालय शाखा ने कारोबार विस्तार के लिए समीर जाधव को 60 लाख रुपये का लोन दिया है। उन्हें यह लोन जेसीबी लिमिटेड से एक नई अर्थ मूविंग मशीन की खरीद के लिए दिया गया। यह उनके कारोबार संचालन की दक्षता को बढ़ाएगी।

समीर जाधव के पास पहले से 5 जेसीबी मशीनें हैं। वे इस व्यवसाय में पिछले चार साल से हैं और अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ये मशीनें उनके कारोबार विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। अपने कारोबार को लगातार आगे बढ़ाने के लिए समर्पित जाधव ने नई जेसीबी मशीन के लिए एनवाईसीएस से संपर्क किया था। एनवाईसीएस ने उनकी विस्तार क्षमता को पहचानते हुए उन्हें लोन मुहैया कराने में मदद की। इस लोन से खरीदी गई नई मशीन से उन्हें बड़ी परियोजनाओं को लेने और बढ़ते ग्राहकों की सेवा करने की उनकी क्षमता को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इससे उन्हें अपने व्यवसाय को बढ़ाने और अपने संचालन को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में सहायता मिली है। यह साझेदारी युवा सशक्तिकरण के प्रति एनवाईसीएस की प्रतिबद्धता को उजागर करती है, जो युवा उद्यमियों को प्रतिस्पर्धी उद्योगों में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक उपकरण और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

एनवाईसीएस के समर्थन से समीर जाधव और भी बड़ी सफलता हासिल करने के लिए तैयार हैं। युवा सशक्तिकरण के तहत उद्यमशीलता और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने से युवाओं की व्यावसायिक और विकास क्षमता में वृद्धि हो रही है।

चोरी से टूटे सपने, एनवाईसीएस ने किए पूरे

महाराष्ट्र के पुणे जिले के उरुली कांचन निवासी शुभम महादिक मोबाइल की दुकान चलाते हैं। साथ ही फोटो कॉपी भी करते हैं।

SAMSUNG
vivo
oppo
mi
iPhone
realme
XEROX / COLOUR XEROX

हाल ही में उन्हें तब बड़ा झटका लगा जब चोरों ने उनकी दुकान को निशान बनाया और दुकान में मौजूद मूल्यवान संपत्तियों और उपकरणों को चुरा ले गए। इस घटना ने उनकी आजीविका को सीधे प्रभावित किया। उनकी आजीविका बहाल करने और उनके व्यवसाय को फिर से खड़ा करने के लिए एनवाईसीएस ने उनकी ओर समर्थन का हाथ बढ़ाया। एनवाईसीएस की उरुली कांचन शाखा ने शुभम को 1.86 लाख रुपये का ऋण दिया जिससे उन्हें अपने व्यवसाय के पुनर्निर्माण में उल्लेखनीय मदद मिली।

एनवाईसीएस की वित्तीय सहायता का उपयोग उन्होंने मोबाइल दुकान के नवीनीकरण और पुनर्निर्माण के लिए किया। वित्तीय सहायता ने उन्हें नए उपकरण खरीदने, दुकान के बुनियादी ढांचे को उन्नत करने और अपने ग्राहकों के लिए अधिक आकर्षक वातावरण बनाने में सक्षम बनाया।

एनवाईसीएस की त्वरित और निर्णायक कार्रवाई से महादिक अब वापस पटरी पर आ गए हैं और अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए तत्पर हैं। एनवाईसीएस की सहायता से उन्हें न केवल अपनी दुकान फिर से बनाने में मदद मिली, बल्कि उनकी उद्यमशीलता यात्रा में उनका आत्मविश्वास भी मजबूत हुआ। अब वह अब अपना व्यवसाय बढ़ाने और ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद और सेवाएं देने के लिए फिर से तैयार हैं। उद्यमियों को चुनौतियों से उबरने और एक उज्जवल भविष्य बनाने के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करके एनवाईसीएस उन्हें सशक्त बनाए रखती है।■

एनवाईसीएस की उरुली कांचन शाखा ने शुभम को 1.86 लाख रुपये का ऋण दिया।

पाटन में त्रिविद कार्यक्रम

હનુમાન
જન નિધિ
સહકાર ભારતી
પાટણ જિલ્લો

नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी (एनवाईसीएस) के 25 वर्ष और सहकार भारती के 46 वर्ष पूरे होने के मौके पर गुजरात के पाटन स्थित खाड़िया मैदान में त्रिविद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान एनवाईसीएस के सदस्यों, एफडी बचतधारकों और पुराने एवं नए कर्मचारियों के लिए एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया।

10 जनवरी, 2025 को आयोजित इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय संगठनों के मंत्री जीवनभाई गोले, सहकार भारती के पाटन जिला अध्यक्ष हरिभाई पटेल, पाटन नागरिक बैंक के पूर्व अध्यक्ष और जिला सहकारी संघ के अध्यक्ष सुरेशभाई पटेल मौजूद रहे। इनके अलावा, बलिया हनुमान जी ट्रस्ट के हरेशभाई व्यास, नगरपालिका अध्यक्ष हिरलबेन परमार और एनवाईसीएस डायरेक्टर हिरेनभाई शाह उपस्थित थे। एनवाईसीएस सहित विभिन्न संगठनों के नेता और शुभचिंतक, जन निधि के सभी स्थानीय डायरेक्टर और कर्मचारी भी इस दौरान मौजूद रहे। विधि ईश्वरभाई परमार ने आभार व्यक्त किया और कार्यक्रम संचालन डॉ. लीलाबेन स्वामी एवं वर्षा बेन सोनी ने किया।

कौशल प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को प्रमाण-पत्र

COOPERATIVE SOCIETY LIMITED

युवा सहकार टीम

कौशल विकास परियोजना के तहत 'हरियाणा में कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं का सशक्तिकरण- आईजीएल की एक सीएसआर पहल' में 330 युवाओं का कौशल प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा हुआ। रेवाड़ी स्थित एनवाईसीएस-कोविडा कौशल विकास केंद्र में आयोजित एक समारोह में इन युवाओं को प्रमाण-पत्र सौंपा गया।

आईजीएल के सहयोग से नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड (एनवाईसीएस) द्वारा चलाए जा रहे इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में युवाओं को एफटीसीपी फील्ड तकनीशियन कंप्यूटिंग और पेरिफेरल्स, डीटीएच- सेट टॉप बॉक्स इंस्टॉलेशन और सर्विस टेकनीशियन और सिटी गैस पाइप फिटर कोर्स के प्रशिक्षण दिए गए। इन पाठ्यक्रमों के माध्यम से युवाओं का सफलतापूर्वक कौशल विकास किया गया। प्रशिक्षण प्राप्त ये युवा अब रोजगार या स्वरोजगार योग्य हो गए हैं। इन युवाओं को 15 जनवरी को कौशल प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र दिया गया।

इस समारोह में एनवाईसीएस की ओर से परियोजना की मुख्य विशेषताओं और प्रमुख उपलब्धियों के साथ परियोजना के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी गई। एनवाईसीएस के महाप्रबंधक अभिषेक कुमार ने अपने विचार साझा करते हुए प्रशिक्षित युवाओं को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दीं और कौशल विकास कार्यक्रम में अपने 15 वर्षों के अनुभव को साझा किया। इन युवाओं को नई दिशा में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने कहा कि कौशल से सशक्त युवा ही विकसित भारत का भविष्य बनेंगे। इस मौके पर भाजपा की जिला अध्यक्ष वंदना पोपली ने युवाओं के साथ अपने विचार साझा करते हुए कहा कि कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से युवा अपने कौशल में सुधार कर सकते हैं। कौशल विकास से लैस युवा नौकरी करने की बजाय खुद नौकरी देने वाले बन सकते हैं।

प्रमाण-पत्र वितरण समारोह के दौरान आईजीएल के सीएसआर प्रमुख पीआर राजेश, एमसी सचिव नरेंद्र यादव, मॉर्लिंग ग्लोबल के निदेशक बिनीत कुमार ने भी अपने विचार साझा किए।■

आईजीएल के सीएसआर प्रोग्राम के तहत हरियाणा में कौशल प्रशिक्षण माध्यम से युवाओं का किया जा रहा सशक्तिकरण, एनवाईसीएस चला रही प्रशिक्षण कार्यक्रम

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
NCDC
Assisting Cooperatives, Always!

LIFIC

LINAC-NCDC FISHERIES BUSINESS INCUBATION CENTER (LIFIC)

For Cooperatives as Fisheries Bussiness

Set up by NCDC at LINAC
under Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY)
Department of Fisheries,
Ministry of Fisheries, AH & D, Govt of India

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
National Cooperative Development Corporation
Ministry of Cooperation, Govt of India

NANO TECHNOLOGY
NANO UREA & DAP

IFFCO
पूर्णतः सहकारी स्वामित्व
Wholly owned by Cooperatives

IFFCO
KISAN
DRONE

असरदार जोड़ी

नैनो यूरिया प्लस

सागरिका

नैनो डी ए पी

IFFCO
NANO
UREA
PLUS
IFFCO
सागरिका
SAGARIKA
100% प्राकृतिक समुद्री उत्पाद
Natural Seaweed Ext
IFFCO
पूर्णतः सहकारी स्वामित्व
Wholly owned by Cooperatives
NANO
DAP
(8:16:0)
CROP NUTRITION REDEFINED
Less Cost, More Profits
Suitable for all Crops

IFFCO
पूर्णतः सहकारी स्वामित्व
Wholly owned by Cooperatives

इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड
इफको सदन, सी-1, डिस्ट्रिक सेंटर, साकेत प्लेस, नई दिल्ली-110017, भारत
फोन नंबर- 91-11-26510001, 91-11-42592626, वेबसाइट www.iffco.coop

इफको नैनो उर्वरकों के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया स्कैन करें"